आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 06.03.2026 समय : 0705

<><><><><><><><>

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से कृषि और ग्रामीण बदलाव पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे।
2. मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने डिगलीपुर का दौरा कर अगले तीन दशकों के लिए 'मास्टर प्लान' तैयार करने पर चर्चा की।
3. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनगणना का पहला चरण, अप्रैल माह से शुरू होगा।
4. श्री विजयपुरम में 9 मार्च से सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जाएगा।

<><><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से कृषि और ग्रामीण बदलाव पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस विषय के तहत आठ वेबिनार सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें चार प्रमुख सेक्टर– कृषि, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालान और ग्रामीण आजीवकिा पर विचार–विमर्श होगा। बजट पश्चात वेबिनार में उच्च मूल्य के कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। वेबिनार में एआई सक्षम कृषि डिजिटल बुनियादी ढांचा– भारत विस्तार से उपलब्ध अवसरों पर भी चर्चा होगी। वेबिनार के सत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश और पशु पालन मूल्य श्रृंखला में उद्यमियता, मत्स्य पालन के लिए जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास, तटवर्ती मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला मजबूत करने तथा स्व–सहायता समूहों की ग्रामीण महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने पर भी चर्चा होगी।

<><><><><><><><>

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग ने सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगी संगठनों, संस्थानों और इच्छुक व्यक्तियों सहित हितधारकों से ज्ञापन और अभ्यावेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसका प्रारूप उपलब्ध कराया है। आयोग के अनुसार अभ्यावेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल पर ही स्वीकार किए जाएंगे और कागजी प्रतियां, ईमेल या पीडीएफ स्वीकार्य नहीं होंगे। आयोग ने हितधारकों से 30 अप्रैल तक अपने ज्ञापन जमा करने को कहा है।

<><><><><><><><>

मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने कल डिगलीपुर का दौरा कर पंचायती राज संस्थान के सदस्यों तथा विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में मध्योत्तर अंडमान जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, मुख्य अभियंता और डिगलीपुर के सहायक आयुक्त भी उपस्थित थे। बैठक में मुख्य सचिव ने भूमि रूपांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर देते हुए कहा कि आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं में हो रही देरी को दूर करने के लिए 'द्वीप भूमि' पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। इस दौरान अगले तीन दशकों के सतत विकास को ध्यान में रखते हुए 'मास्टर प्लान' तैयार करने पर चर्चा हुई। इसमें स्थानीय लोगों और हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए उपयुक्त सरकारी भवनों की पहचान करने, पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी पंचायतों, सरकारी संस्थानों और स्कूलों में फील्ड टेस्टिंग किट का प्रदर्शन करने और निवासियों को प्रशिक्षित करने, पंचायतों को 'गौशाला' स्थापित करने, उत्तर और मध्य अंडमान को जोड़ने वाले ग्रिड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और युवाओं के व्यक्तिगत विकास के लिए खेल गतिविधियों के महत्व पर जोर दिया गया। उन्होंने पंचायतों द्वारा निर्मित रिंग वेल की मैपिंग और पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए अंडमान लोक निर्माण विभाग को निर्देश भी दिए।

<><><><><><><>

द्वीपों के सांसद बिष्णु पद रे ने दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत कालीकट, सिप्पीघाट, गुप्तपाड़ा, वांडूर, हम्फ्रीगंज, टुशनाबाद, मीठाखाड़ी और नमुनाघर ग्राम पंचायतों में 11 स्थानों पर ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण, सुधार और चौड़ीकरण कार्य की आधारशिला रखी। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, जिला परिषद सदस्य, पंचायती राज संस्थानों के सदस्य, संबंधित क्षेत्रों के प्रधान, अंडमान लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और स्थानीय निवासी उपस्थित थे। इस दौरान सांसद ने कहा कि क्षेत्र की कई ग्रामीण सड़कें वर्तमान में जर्जर स्थिति में हैं। स्वीकृत कार्यों से इन सड़कों का उचित चौड़ीकरण और नवीनीकरण होगा, जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनगणना का पहला चरण, अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, 31 जनवरी की गजट अधिसूचना के अनुसार स्व–गणना पहली अप्रैल से 15 अप्रैल तक और मकान सूचीकरण कार्य 16 अप्रैल से 15 मई तक किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, 'जनगणना 2027' के मकान सूचीकरण कार्य के लिए नियुक्त प्रगणक प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और 33 प्रश्नों पर आधारित जानकारी एकत्र करेंगे। डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रगणकों के लिए जनगणना कार्यालय की ओर से चरणबद्ध

प्रशिक्षण का पालन किया जा रहा है। द्वीपसमूह में मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण पहले ही पूरा हो चुका है। दक्षिण अंडमान में फील्ड ट्रेनर्स के लिए कल से तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। अगले सप्ताह मध्योत्तर अंडमान और निकोबार जिले के फील्ड ट्रेनर्स को भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

<><><><><><><>

श्री विजयपुरम में 9 से 23 मार्च तक सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष और न्यायाधीश चैताली चटर्जी (दास) बैठक की सुनवाई करेंगे।

<><><><><><><>

जहाज सिंधु 18 मार्च को सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए कोलकाता के लिए रवाना होगा। इस यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग आज से शुरू हो रही है। यात्री विभाग के ई–टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए पोर्टल का क्यू आर कोड भी उपलब्ध कराया गया है। ऑफलाइन टिकटों की बुकिंग सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जबकि शनिवार के दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्टार्स टिकटिंग काउंटर से कराए जा सकते हैं।

<><><><><><><>

आई.सी.डी.एस. परियोजना, रंगत के अंतर्गत मायाबंदर के लटाव आंगनवाड़ी–सह–क्रेच केंद्र में एक आंगनवाड़ी–सह–क्रेच कार्यकर्ता के रिक्त पद के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। आवेदन 12 मार्च शाम 5 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, रंगत के पते पर किया जा सकता है। इस पद के लिए संबंधित क्षेत्र के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन पत्र और अन्य जानकारियां समाज कल्याण निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

<><><><><><><>

'प्रशासन गांव की ओर – संपर्क से समाधान' कार्यक्रम के तहत कल डिगलीपुर स्थित सहायक आयुक्त कार्यालय में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। मध्योत्तर अंडमान जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर के दौरान अधिकारियों द्वारा कई लंबित राजस्व मामलों की सुनवाई और निपटारा किया गया। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

<><><><><><><>

अंडमान लोक निर्माण विभाग, रंगत की टीम की ओर से हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को जल संसाधनों के संरक्षण के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना और पानी के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर जल संरक्षण और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के महत्व को दर्शाने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। जीरो लीकेज पहल के तहत पानी से संबंधित शिकायतों के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अभियंता, सहायक आयुक्त, उपाध्यक्ष और प्रमुख ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। जल आपूर्ति से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम से संपर्क किया जा सकता है।

<><><><><><><>